University in News on 02 January 2021

TOI PAGE 2

LU students hail re-evaluation move

Times News Network

Lucknow: Students have welcomed the decision of Lucknow University to allow "challenge re-evaluation" of examination answer copies which will enable them to clear all doubts about allotment of marks.

The system was approved in the examination committee meeting held recently under which if students are not satisfied with their marks, they can opt for rechecking. Re-evaluation will be done after a student submits an application along with the required fee. The result will be informed to the student via email.

Though the fee for re-evaluation will be announced soon, sources said it could be around Rs 2,500.

If the difference of marks before and after re-evaluation is 20% or more, action will be taken against the teacher who checked the copy earlier.

"Earlier, the only option to see answer copies was through Right to Information which was a cumbersome process. Moreover, one could only see the copy under the arrangement and could not get it rechecked," said Vishal Singh, a student of MA (Applied Economics). He said the system would bring more transparency in the evaluation process.

Some students, however, felt that if Rs 2,500 are charged as fee, it would be an expensive option, considering the socio-economic background of a section of students. "The move is good but the biggest drawback is the high fee, which everyone will not be able to afford," said BA student Gauri Srivastava.

LU officials said the fee in other universities was Rs 5,000 or above.

"We have put a provision of fee so that only student with genuine concerns apply for challenge re-evaluation, otherwise there will be a flood of applications which will derail the entire process," a senior officer said.

HOW TO APPLY

- **STEP 1** | Register on LU examination portal
- **STEP 2** | Fill in details such as roll number, subject, etc
- **STEP 3** | Upload fee receipt to challenge re-evaluation

AMRIT VICHAR PAGE 2

बीएड में सीधे प्रवेश प्रक्रिया हुई समाप्त

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से शुरू हुई बीएड प्रवेश प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। इस बात की जानकारी बीएड कोआर्डिनेट प्रोफेसर अमिता बाजपेयी ने दी है। उन्होंने बताया कि कुल उपलब्ध 2 लाख 44 हजार 701 सीटों के सापेक्ष कुल 1 लाख 83 हजार 909 अभ्यर्थियों को उनके वांछित बीएड महाविद्यालयों में सीट आवंटित हुई है। पूर्व में यह काउन्सिलिंग 27 दिसम्बर तक ही निर्धारित थी लेकिन अभ्यर्थियों के उत्साह व उनके व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय स्तर से सीधे प्रवेश की प्रक्रिया को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। प्रोफेसर अमिता बाजपेयी कि काउन्सिलिंग का यह अंतिम चक्र था जिसमें महाविद्यालयों की ओर से लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी को सीधे प्रवेश दिया गया। प्रवेश शुल्क महाविद्या लय स्तर पर ही जमा करने की सुविधा दी गई।

AMAR UJALA MY CITY PAGE 5

लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ने वाले चार जनपदों के महाविद्यालयों में होगा बदलाव

कॉलेजों में दोगुनी तक बढ़ सकती है फीस

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ने वाले चार जनपद के कॉलेजों के लिए नए सत्र से काफी कुछ बदलने वाला है। बदलाव का सबसे ज्यादा असर छात्रों की फीस पर पड़ेगा। अभी तक इन कॉलेजों में वार्षिक प्रणाली लागू थी, जबकि लविवि में सेमेस्टर प्रणाली है। विश्वविद्यालय से सहयुक्त होने के बाद यहां भी सेमेस्टर प्रणाली लागू हो जाएगी। ऐसे में विवि से जुड़ने वाले कॉलेज के विद्यार्थियों को भी साल में दो बार फीस देनी होगी। लविवि की परीक्षा फीस भी कानपुर विवि के मुकाबले ज्यादा है। ऐसे में इन कॉलेजो को विद्यार्थियों से पहले के मुकाबले करीब चार गुना परीक्षा फीस वसूलनी होगी। कुल फीस पर इस तरह कॉलेजों को करीब दो गुना फीस बढ़ानी पड़ सकती है।

लखनऊ विश्वविद्यालय से इस साल हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और लखीमपुर जिले के कॉलेज सहयुक्त किए गए हैं। अभी तक ये कॉलेज कानपुर विवि से सहयुक्त थे। कानपुर विवि में परीक्षा फीस केवल एक हजार रुपये है। यह फीस सिर्फ साल में एक बार देनी होती है। वहीं, लखनऊ विश्विद्यालय की परीक्षा फीस न्यूनतम दो हजार रुपये प्रति सेमेस्टर है। साल में दो सेमेस्टर के हिसाब से विद्यार्थी को कम से कम चार हजार रुपये परीक्षा फीस के ही देने होंगे। इस तरह सिर्फ परीक्षा फीस की बात करें तो पहले के मुकाबले विद्यार्थियों को चार गुने ज्यादा भुगतान करना होगा। कुल फीस पर यह अंतर दो गुने से ज्यादा ही होगा। ऐसे में कॉलेजों के सामने फीस बढ़ाना मजबूरी होगी।

कॉलेजों के प्रस्ताव पर किया जा सकता है विचार

लविवि की परीक्षा फीस ज्यादा होने की बड़ी वजह आर्थिक तंगी है। लविवि का अनुदान फ्रीज होने की वजह से विवि को सरकार से सिर्फ 34 करोड़ रुपये का अनुदान मिलता है। बाकी की व्यवस्था लविवि को अपने स्रोतों से करनी होती है। शासन की बिना अनुमति के लविवि अपनी फीस भी नहीं बढ़ा सकता है। ऐसे में लविवि परीक्षा फीस बढ़ाकर अपने खर्चों की भरपाई कर लेता है। लविवि से इस समय 176 कॉलेज सहयुक्त हैं। चार जनपद के कॉलेज जुड़ने पर इससे करीब 360 कॉलेज और जुड़ जाएंगे। इन कॉलेजो से मिलने वाली परीक्षा फीस की राशि काफी हो जाती है। लविवि के सूत्रों के अनुसार कॉलेजों की ओर से परीक्षा फीस पर कोई प्रस्ताव मिलने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादा कॉलेज होने पर परीक्षा फीस की राशि इतनी हो जाएगी, जिससे कि आसानी से परीक्षा आयोजित हो सकें।

विवि से संपर्क में जुटे

लखनऊ विवि से जुड़ने वाले कॉलेज के संचालकों की हालत इस समय खराब है। कॉलेज संचालक लविवि से संपर्क करके परीक्षा फीस का आंकलन कर रहे हैं। जुलाई में शुरू होने वाले अगले सत्र में ये इन कॉलेजों के दाखिले लविवि से सहयुक्त हो जाएंगे। इसलिए इन कॉलेजों को अपनी फीस अभी से निर्धारित करनी होगी।

VOICE OF LUCKNOW PAGE 3

लविवि में आगामी सत्र से होंगे डीलिट के दाखिले

वरिष्ठ संवाददाता (vol)

लखनऊ। लविवि में आगामी सत्र से डीलिट के दाखिले शुरू हो रहे हैं। यह दाखिले गत दस वर्षों बाद शुरू हो रहा है। पिछले दस सालों से डीलिट का इंतजार कर अभ्यर्थियों के लिए यह राहत भरी खबर है। उन्हें लविवि से डीलिट करने का मौका मिलेगा। फिलहाल इसकी कार्ययोजना ही तैयार की गयी है। अभी तक यह निर्णय नहीं हो पाया है कि कितनी सीटों पर दाखिले लिये जायेंगे। पीचएडी करने के बाद बहुत से छात्र-छात्राओं का सपना होता है कि वे डीलिट भी कर सकें। ऐसे में बहुत से लोगों ने लविविको अपनी पहली पंसद बना रखा है लेकिन विगत दस वर्षों से डीलिट में कोई दाखिला न होने के कारण लोग काफी मायूस थे। विवि की लचर व्यवस्था के कारण दस वर्षों से लोगों को डीलिट करने का इंतजार करना पड़ा। अभी वर्तमान कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने डीलिट को लेकर अध्यादेश तैयार कर दिया है। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि विवि को लगातार नित नयी ऊचाईयों पर ले जाने के लिए सभी ओर ध्यान दिया जाना जरूरी है। ऐसे में डीलिट को छोड़ा नहीं जा सकता था इसलिए डीलिट के लिए अध्यादेश पूरा कर लिया गया है और अगले वर्ष से सबसे पहले डीलिट के प्रवेश शुरू होंगे।

● दस साल बाद शुरू हो रही प्रवेश प्रक्रिया

बीएड की 75 फीसदी सीटों पर हुए दाखिले

लखनऊ। लविवि द्वारा विगत अगस्त माह में आयोजित की गयी उप्र संयुक्त प्रवेश-परीक्षा बीएड-2020-22 की महाविद्यालय स्तर से सीधे प्रवेश की प्रक्रिया में बीते 31 दिसम्बर को समाप्त हो गई। इस दौरान कुल सीटों के सापेक्ष 75.16 फीसदी सीटों पर प्रवेश हो पाया। लगभग 25 प्रतिशत सीटें खाली रह गयी। कुल उपलब्ध 2,44,701 सीटों के सापेक्ष कुल 1,83,909 अभ्यर्थियों को उनके वाँछित बीएड महाविद्यालयों में सीट आवंटित हुई है। पूर्व में यह काउंसिलिंग 27 दिसम्बर, 2020 तक ही निर्धारित थी लेकिन अभ्यर्थियों के उत्साह व उनके व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय स्तर से सीधे प्रवेश की प्रक्रिया को दिनांक 31 दिसम्बर तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया। संयुक्त प्रवेश-परीक्षा बीएड-2020-22 की राज्य-समन्वयक प्रो. अमिता बाजपेयी ने अवगत कराया है कि काउंसिलिंग का यह अंतिम चक्र था जिसमें महाविद्यालयों द्वारा लविवि की वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी को सीधे प्रवेश दिया गया। प्रवेश शुल्क महाविद्यालय स्तर पर ही जमा करने की सुविधा दी गयी।